

पहले मुख्य समाचार।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश के पहले स्वदेशी 4जी नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लखनऊ से देखेंगे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे तक लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण समेत बाइस प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की देर रात की समीक्षा। कहा-कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर करें कठोर कार्रवाई।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले चौबीस नये न्यायाधीश। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर की नियुक्ति।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश के पहले स्वदेशी 4जी नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही भारत दुनिया का पांचवां ऐसा देश बन जाएगा, जो अपना पूर्ण स्वदेशी 4जी टेलीकॉम स्टैक विकसित और लागू करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लखनऊ में देखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट-

ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टॉवरों का उद्घाटन करेंगे, इस क्रांतिकारी कदम से उत्तर प्रदेश के अब तक नेटवर्क से कटे 240 गांवों के 24 हजार से अधिक लोग पहली बार हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएंगे। यह महत्वाकांक्षी पहल प्रदेश के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुंचाएगी, जहां अब तक या तो मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी या फिर लोग केवल 2जी नेटवर्क तक ही सीमित थे। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक यूपी ईस्ट अरुण कुमार गर्ग ने बताया कि प्रदेश में बीएसएनएल ने अब तक छः हजार छः सौ उनसठ साइट्स पर फोर-जी सेवाएं स्थापित कर दी हैं। यूपी में भारत-नेपाल सीमा पर बीएसएनएल की अड्सठ साइट्स मंजूर की गयी हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण समेत 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई।

बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिला खनिज फाउंडेशन-डीएमएफ न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दे दिया है। संशोधन के तहत जिला खनिज फाउंडेशन निधि का 70 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा। शेष 30 प्रतिशत निधि का उपयोग भौतिक संरचना विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली-दीपावली के अवसर पर 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थी परिवारों को दो निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) के निर्माण को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की घोषणा की है। अन्य प्रमुख फैसलों में वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से वंचित रह गए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण समारोह के अंतर्गत 3 लाख 96 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 89 करोड़ 96 लाख रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2025-26 में प्रदेश में छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वन नेशन वन-स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी लागू करने जा रहे हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कल गाजियाबाद के एक निजी शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी देश के युवाओं के ऊपर है। वहीं जीएसटी सुधारों को देशहित में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

जीएसटी अत्यंत ग्रहण हुआ है। समाज में जीएसटी आज सरल हो चुकी है। चार स्लैब से ये दो स्लैब तक पहुंच चुकी है। अनेक चीजों में सामान्य लोगों की गरीबों की, मध्य वर्गीयों की विशेष करके विद्यार्थियों की अनेक रोजमर्रा की आवश्यकता है। जीरो टैक्स ब्रेकेट में आ चुका है। नोटबुक जीरो टैक्स पर आ गया है। पेंसिल जीरो टैक्स पर आ गया है। इनमें से पढ़ाई बढ़ेगी। लोग आगे बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों एवं जोनल एडीजी के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट—

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पर्व त्योहारों के अवसर पर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में कुछ स्थानों पर हुई घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि यह सब प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। आयोजकों और मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की जांच हो। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।

इलाहाबाद हाई कोर्ट को 24 नये न्यायाधीश मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नये न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन 24 न्यायाधीशों में 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।

सरकार, सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला – सेवा पर्व में, आज बात करेंगे कि मोदी सरकार ने कैसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट—

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ब्रह्मांड के साथ भारत का जुड़ाव अभूतपूर्व उपलब्धियों की एक कहानी में बदल गया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक पापुलेशन जैसी आवश्यक अंतरिक्ष तकनीकों में तेजी से प्रगति हुई है। जनवरी में भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष की सफल यात्रा भारत की पहली मानव अंतरिक्षयान गगनयान की सफलता की दिशा में पहला कदम है। वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है। यह सफलता मोदी सरकार के नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है। जिसमें अंतरिक्ष तकनीक के विकास में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की कम दर नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट—

नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने पहले के चार श्रेणी ढांचे 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत को दो श्रेणी में सरल कर दिया है, जो 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत है। 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने क्षमता वाली बसों पर जीएसटी कटौती 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। जीएसटी दर कम होने से बसों और मिनी बसों की लागत में कमी आएगी। जीएसटी दर कम करने से टिकट किराए को घटाने में भी मदद मिलेगी, खासकर अर्धशहरी और ग्रामीण मार्गों पर। जीएसटी परिषद ने साढ़े 300 सीसी तक की छोटी कारों और दो पहिया वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। जिन पर पहले जीएसटी दर 28 प्रतिशत हुआ करता था। कम जीएसटी से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए छोटी कारें अधिक सस्ती हो जाएंगी। शिवांग के साथ दृष्टि पुनियानी आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

प्रदेश के एमएसएमई, खादी, हथकरघा और वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने कल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित भारत-रूस बिजनेस डायलॉग को संबोधित किया। श्री सचान ने कहा कि यह आयोजन दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विजन से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
